

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4203  
गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

ज्वारीय तरंगों से विद्युत

4203. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उत्पादित की जा सकने वाली ज्वारीय विद्युत की संभावित क्षमता कितनी है;
- (ख) अब तक इस क्षमता का किस हद तक दोहन किया गया है;
- (ग) क्या देश में अपार संभावना होते हुए भी देश में ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन में सरकार असफल रही है;
- (घ) क्या सरकार ने एक अध्ययन के माध्यम से ज्वारीय तरंगों से विद्युत की संभावना का आकलन किया है और इसके संभावित ज्वारीय स्थानों का पता लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार के पास ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पादन की कोई राष्ट्रीय नीति है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) क्या सरकार का ऐसी नीति बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ज्वारीय विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (च): दिसंबर 2014 में क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साल्यूशंस लिमिटेड के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा आयोजित एक अध्ययन के अनुसार देश में ज्वारीय विद्युत संभाव्यता लगभग 12455 मेगावाट है। निम्न/मध्यम ज्वारीय तरंग शक्ति वाले संभावित क्षेत्र खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु में पाल्क बे मन्नार चैनल और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरवन में है।

ज्वारीय शक्ति के दोहन के लिए पहले के प्रयास 30 करोड़ रूपए से लेकर 60 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट की उच्च पूंजी लागत की वजह से सफल नहीं हो पाए थे।

वर्तमान में बहुत अधिक पूंजीगत लागत के कारण भारत सरकार ने ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

\*\*\*\*\*